and no money could be paid. Those quarters are supposed to be transferred to the EPF workers and, to that effect, a note was circulated by the Ministry to the Provident Fund Trustee Board and no decision has taken by the Trustee Board despite the fact that the Ministry was interested to push through the scheme without the decision of the CVT and transfer those rejected quarters constructed by the HUDCO. No payment has been made to the contractors and contractors ought to be paid from the provident fund of the employees.

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, "हुडको" के कोई ऐसे 10 हजार मकान नहीं हैं जिनको लेने की हमारी योजना है।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, there are reports in different newspapers that the Employees Provident Fund Authority is not functioning in the manner it should function and there are many complaints of swindling the money of the workers by different employers and in collusion, perhaps, with the EPF authorities in different regions. Will the Minister respond that whether the Government is taking some stringent action against such situation and to ameliorate the conditions of the workers?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, मूल प्रश्न से यह सवाल उत्पन्न नहीं होता है।

श्री सभापति: ठीक है।

सेल्यूलर टेलीफोन

*427. **श्री हरीश रावत**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में ऐसे कितने जिले हैं जहां सेल्यूलर टेलीफोन सेवाएं नहीं हैं;

(ख) क्या इन जिलों में सेल्यूलर टेलीफोन सेवाओं के लाभ पहुंचाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सेल्यूलर प्रचालकों की ओर से सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया से प्राप्त सूचना के अनुसार देश के 201 जिलों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) उपलब्ध नहीं है। तथापि, देश में जिस तेजी से दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए उपर्युक्त आंकड़ों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लि॰ और महानगर टेलीफोन निगम लि॰ जैसे सरकारी प्रचालकों को पूरे देश के लिए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। सरकारी प्रचालकों ने सभी जिलों में 2003-04 तक सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने की योजनाएं बनायी हैं। प्राइवेट सेल्यूलर ऑपरेटरों ने अपने-अपने लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में उक्त सेवा प्रदान करने के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं।

Cellular telephones

†*427. SHRI HARISH RAWAT: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the number of districts in the country without the cellular telephone services;

(b) whether the benefits of cellular telephone services are to be extended to these districts; and

(c) if so, by when?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the current information available from Cellular Operators Association of India on behalf of Cellular Operators, 201 districts in the country are without Cellular Mobile Telephone Service (CMTS). However, due to fast expanding telecom networks in the country, above figure changes continuously.

(b) and (c) The Government operators, namely, Bharat Sanchar Nigam Limited and Mahanagar Telephone Nigam Limited have been granted CMTS Licences covering whole of the country. The Government Operators

†Original notice of the question was received in Hindi.

have made plans to cover all the districts with CMTS by 2003-2004. The private Cellular Operators have individual plans to cover their respective licensed Service Areas.

श्री हरीश रावत: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 201 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी तक सेलुलर सेवा का विस्तार नहीं हो पाया है या वे लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, ऐसे कई राज्य भी हैं जिनमें अभी भी यह सेवा उपलब्ध नहीं है, जम्मू-कश्मीर का अभी जिक्र आया और इस तरीके से कुछ और भी हैं जिन्हें दुर्भाग्यशाली समझिए या वंचित राज्य समझिए। उन राज्यों में या ऐसे क्षेत्रों में, कब तक आप इस सेवा का विस्तार कर देंगे, क्योंकि इस सेवा के विस्तार के लिए उन क्षेत्रों में प्राइवेट ऑपरेटर्ज़ तो जायेंगे नहीं, केवल बीएसएनएल और सरकारी एजेंसीज़ ही जा सकती हैं। उन एजेंसीज़ को क्या आप डाइरेक्ट करेंगे कि वे जल्दी से जल्दी इन क्षेत्रों में इस सेवा की कवरेज बढ़ाएं?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, जैसे सदन को यह बात ज्ञात है कि भारत संचार निगम के सारे देशभर में मोबाइल सेवा ले जाने के निर्णय करने के पहले मोबाइल सेवाएं केवल निजी क्षेत्र में थीं। वे कितने जिलों में पहुंचीं, यह कार्य भी, जब आपने प्रश्न पूछा, तब हमने निजी क्षेत्रों से संपर्क करके अनुमान लगाया कि 201 जिलों में अभी तक ये सेवाएं नहीं पहुंची हैं। स्वाभाविक रूप से ये सेवाएं वहां उन्होंने जल्दी शुरू की हों जहां कि लाभ हो। लेकिन अब भारत संचार निगम इसमें आया है और जैसे मैंने उत्तर में ही आपको कहा है कि 2003-04 अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक हिन्दुस्तान का एक भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जहां कि मोबाइल सेवा शुरू नहीं होगी। यह हमारा प्रयास होगा कि अगले सवा साल में देश के हर जिले में भारत संचार निगम की मोबाइल सेवा हो और मैं आशा करता हूं कि तब तक निजी क्षेत्र भी कुछ और आगे जायेंगे जो 201 जिले बचे हैं, हो सकता है उनमें भी वे चले जाएं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि 31 मार्च, 2004 तक देश के सभी जिलों में सबको मोबाइल सेवा मिलेगी।

श्री हरीश रावत: सर, आपने 2003-04 तक मोबाइल सेवा के विस्तार करने की जो बात कही है उसके लिए आपको धन्यवाद। अब जिले तो आप कवर कर लेंगे मगर अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, विशेषकर उत्तरांचल में कई तहसील हेड क्वार्टर ऐसे हैं, जहां कि आप जानते हैं कि वहां कई महत्वपूर्ण यात्रा लाइनें हैं जिसमें कैलाश मानसरोवर भी है, बद्रीनाथ की भी है, चारों धामों की यात्रा है, अभी तक उन क्षेत्रों में एसटीडी की सेवाओं का विस्तार नहीं है और वही पुरानी परंपरागत प्रणाली वहां पर काम कर रही है जिससे देशभर के यात्रियों को भी कठिनाई होती है और वे क्षेत्र भी अपने आपको डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर सबसे उपयोगी प्रणाली जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे डब्ल्यूएलएल प्रणाली शुरू हो सकती है, क्या उसके लिए आप कुछ एशोयर कर सकते हैं कि कब तक उन क्षेत्रों में उस प्रणाली का लाभ मिलेगा?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, मानसरोवर तक तो कोई प्रणाली ले जाने का हमारा इरादा नहीं है।

श्री हरीश रावत: मैंने यात्रा रूट की बात कही है।

श्री प्रमोद महाजन: यात्रा रूट पर भी सब जगह तो नहीं, लेकिन हमारी यह कोशिश है जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यूएलएल सेवा के द्वारा हर गांव तक टेलीफोन पहुंचे, यह हमारी कोशिश है। यह डब्ल्यूएलएल सेवा की जो बात हम कर रहे हैं यह सेवा मोबाइल नहीं है। अभी आपने पहले मोबाइल सेवा का पूछा था, यह फुल मोबिलिटी वाली सेवा नहीं है, यह लिमिटेड गांवों तक पहुंचने की योजना है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा प्रयास है और जैसे आपने कहा कि जो तीर्थ क्षेत्र हैं या वहां जाने के जो रास्ते हैं तो उस संबंध में कहना मुश्किल है क्योंकि रास्ते पर सब जगह टॉवर लगाना, और उसका बिजनैस प्रोपोज़ल भी देखना पड़ेगा, लेकिन जो तीर्थ क्षेत्र हैं बड़े-बड़े तीर्थ क्षेत्र जो उत्तरांचल में आते हैं वहां पर फोन का जाना और वहां से एसटीडी सेवा यात्रियों को मिलना या बीच में बड़े स्थानों पर मिलना, यह संभव हो सकता है, लेकिन सारे रास्ते पर करना यह लगता नहीं कि वह संभव होगा।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, the Minister has stated that the private cellular operators have their individual plans to cover the respective licence service areas. Is there any scheme for monitoring their plans to cover the entire licence service area? Or they will just go haywire and whenever they want, they will have it!

SHRI PRAMOD MAHAJAN: The private cellular operators have a minimum roll-out plan. Beyond the minimum roll-out plan, it is their business plan. The Ministry does not have any system whereby we can monitor their business plan. It is very difficult for us to get information from them. There are a large number of operators. As I said, we are not depending only on the private operators to go to the entire country. We hope that BSNL will take care of large part of the country, and I would like to say one thing, Sir, that we cannot give a time. But, I am sure the way in which the technology is moving, four or five years down the line, the whole India, from Dwarka to Kamakhya and from Katra to Kanyakumari, you will have almost an umbrella of bandwidth where everybody will be entitled to make a telephone call in the moving technology. Now, we cannot give a timeframe because from five or seven years down the line, I do not find any village or any major road in this country which will not have the mobile service.

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि समाज का कौन-सा वर्ग सबसे ज्यादा सेलुलर फोन इस्तेमाल करता है?

श्री प्रमोद महाजन: संभवत: एम०पीज़०। क्योंकि इसीलिए यहां पर फोन को यूस करना बैन किया गया है।

Non-remittance of provident fund contribution

*428. SHRI J. CHITHARANJAN†:

SHRI MOTILAL VORA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number as well as the names of the employers and companies that have defaulted in remitting the provident fund contribution to EPF during the last two years;

(b) the action taken to realise the arrears;

(c) what action has been taken against those defaulting employers and companies;

(d) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Kai Sal Se P.F. Ki Rakam Jama Nahin Karai" appearing in the 'Rashtriya Sahara' dated the 30th June, 2002;

(e) if so, the action taken in the matter?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA) (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Some of the establishments have defaulted in the payment of statutory Provident Fund dues throughout the country. The number of establishments who have defaulted for an amount of Rs 10 lakhs or more is 845 in 2000-2001 and 863 in 2001-2002, and a large number of establishments have defaulted for an amount below Rs. 10 lakhs. It is not possible to furnish a list of all defaulting establishments as this list will be too large. As on 31-3-2002, the total default was Rs. 1336 crores, out of which 77.32% is currently unrealisable being the amount locked up in court stays, establishments registered with BIFR, etc. The default constitutes only 1.3% of total holding of Rs. 1,02,163.06 crore in

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. Chitharanjan.